

प्रेषक,

सौरभ जैन,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

- 1- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तराखण्ड।
- 2- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

- 3- अध्यक्ष,
विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण
देहरादून/नैनीताल/गंगोत्री।
- 4- उपाध्यक्ष,
विकास प्राधिकरण
देहरादून/हरिद्वार।

देहरादून, दिनांक 20 अगस्त, 2008

आवास विभाग

विषय : उत्तराखण्ड में स्थित नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-1803/V-आ0-2005-187(आ0)/01टी0सी0-1 दिनांक 4-8-2005 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड में स्थित नजूल भूमि के प्रबन्ध एवं निस्तारण हेतु उत्तराखण्ड नजूल नीति निर्गत की गयी थी। उक्त शासनादेश के प्रस्तर-27 के अनुसार नजूल नीति निर्गत होने से दो वर्ष अर्थात् दिनांक 3-8-2007 तक लागू रहने की व्यवस्था निर्धारित थी।

2- तदुपरांत शासनादेश सं0-492/V-आ0-2008-187(आ0)/01टी0सी0-1 दिनांक 18-3-2008 द्वारा नजूल नीति लागू रहने की अवधि दिनांक 31-7-2008 तक बढ़ाये जाने के निर्देश निर्गत किये गये।

3- तत्पश्चात शासन के संज्ञान में यह बात आयी है कि नजूल भूमि फ्रीहोल्ड के ऐसे प्रकरण भी लम्बित हैं, जिनमें दिनांक 31-7-2008 तक आवेदकों से फ्रीहोल्ड हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हो चुके हैं। ऐसे प्रकरणों पर सम्यक विचारोपरांत लिये गये निर्णयानुसार मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नजूल भूमि फ्रीहोल्ड के ऐसे लम्बित प्रकरण जिनमें दिनांक 31-7-2008 तक फ्रीहोल्ड हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हो चुके हैं, को नजूल नीति के शासनादेश दिनांक 4-8-2005 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत नियमानुसार निस्तारण करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सौरभ जैन)
अपर सचिव

संख्या 1511 (6) 187(आ0)/01टी0सी0-I तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित -

- 1- समस्त स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड।
- 2- निदेशक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय।
- 3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(एस0के0 पंत)
अनु सचिव